बीएसएनएलईयू के स्थापना दिवस के अवसर पर।

बीएसएनएल ट्रेड यूनियन आंदोलन की झलकियाँ।

वर्ष 2007। श्री ए राजा, केंद्रीय संचार मंत्री थे। उन्होंने बीएसएनएल द्वारा 45 मिलियन लाइन मोबाइल उपकरणों की खरीद के लिए जारी निविदा को रद्द करने का निर्देश जारी किया। दूरसंचार ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में पहली बार, बीएसएनएल के सभी कर्मचारी और अधिकारी एकजुट हुए और 45 मिलियन लाइन निविदा को रद्द करने का विरोध करते हुए 11 जुलाई, 2007 को एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल पूरी तरह और ऐतिहासिक रूप से सफल रही। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि, बीएसएनएलईयू ने पहल की और इस ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व भी किया। इस हड़ताल के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल को उस निविदा से 22.5 मिलियन मोबाइल लाइन उपकरण खरीदने की अनुमति मिली।

वर्ष 2009। संचार मंत्री, श्री ए राजा ने सभी यूनियनों और एसोसिएशनों की बैठक में बीएसएनएल में आईपीओ शुरू करने के अपने निर्णय की जानकारी दी। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो विनिवेश के अलावा कुछ नहीं है। मंत्री ने नेताओं से कहा कि वे सभी बीएसएनएल कर्मचारियों को शेयर आवंटित करेंगे और उनमें से प्रत्येक को 'लखपति' बनाएंगे। लेकिन सभी यूनियनों और एसोसिएशनों ने मंत्री के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। इससे मंत्री को आईपीओ प्रस्ताव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले दिन, *द इकोनॉमिक टाइम्स* ने खबर प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि यूनियनों और एसोसिएशनों के कड़े विरोध के कारण बीएसएनएल में आईपीओ प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। इस आईपीओ को रोकने में बीएसएनएलईयू ने प्रमुख भूमिका निभाई।

वर्ष 2010। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। समिति ने बीएसएनएल के 30 प्रतिशत शेयरों की 'रणनीतिक बिक्री' एक निजी पार्टी को करने और उस निजी पार्टी को बीएसएनएल के 'रणनीतिक भागीदार' के रूप में शामिल करने की सिफारिश की। यह बीएसएनएल के आंशिक निजीकरण के अलावा और कुछ नहीं था। बीएसएनएलईयू ने इसके खिलाफ सभी यूनियनों और एसोसिएशनों को लामबंद किया और 01.12.2010 से बीएसएनएल में 3 दिवसीय हड़ताल हुई। यूनियनों और एसोसिएशनों और दूरसंचार सचिव के बीच बातचीत हुई। इसके परिणामस्वरूप, तीसरे दिन हड़ताल वापस ले ली गई। बीएसएनएल के 30 प्रतिशत शेयरों की रणनीतिक बिक्री के लिए सैम पित्रोदा समिति का प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

वर्ष 2012। यूनियनों और एसोसिएशनों तथा बीएसएनएल प्रबंधन के बीच 78.2 प्रतिशत आईडीए विलय के संबंध में समझौता हुआ। बीएसएनएल प्रबंधन ने प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग की मंजूरी के लिए भेजा। लेकिन, एक पूरे वर्ष तक दूरसंचार विभाग ने बिना किसी मंजूरी के फाइल को दबाए रखा। बीएसएनएलईयू ने यूनियनों और एसोसिएशनों को अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद किया। 12.06.2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नोटिस जारी किया गया। पूरे देश में शानदार लामबंदी की गई। परिणामस्वरूप, दूरसंचार विभाग ने 10.06.2013 को 78.2 प्रतिशत आईडीए विलय के लिए आदेश जारी किया। इसके परिणामस्वरूप, हड़ताल वापस ले ली गई।

नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में नव–उदारवादी नीतियों को लागू किया। सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण नव–उदारवादी नीतियों के स्तंभों में से एक है। इन नव–उदारवादी नीतियों के कार्यान्वयन में, वर्ष 2000 में, वाजपेयी सरकार ने बीएसएनएल का गठन किया। इसके पीछे विचार बीएसएनएल में तुरंत विनिवेश शुरू करना और अंततः इसका निजीकरण करना था।

लेकिन, लगभग 25 साल पूरे होने के बाद भी, बीएसएनएल 100 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी हुई है। इसकी वजह बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिवों और नॉन–एग्जीक्यूटिवों की एकता और संघर्ष है। बीएसएनएलईयू ने बीएसएनएल और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी यूनियनों और एसोसिएशनों को एकजुट करने और उनका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि बीएसएनएल कर्मचारियों ने लगातार 8 बार बीएसएनएलईयू को नंबर एक मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में चुना है।

****